संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 18 मई, 2018 : ज्येष्ठ शुक्ल 3 वि. 2075

मानसिक दृढ़ता सबसे मजबूत हथियार है

बिना नियमों वाला खेल

खंडित जनादेश राजनीतिक दलों को किस तरह मनमानी का अवसर देता है, इसका ही गवाही दे रहा है कर्नाटक का राजनीतिक परिदृश्य। कर्नाटक में जैसा जनादेश आया उसमें किसी भी दल के लिए यह संभव ही नहीं कि वह बिना जोड़-तोड़ सरकार बना सके। कांग्रेस ने जैसे ही यह देखा कि भाजपा सबसे बड़े दल के रूप में उभरने के बाद भी बहुमत तक नहीं पहुंच पाएगी उसने आनन-फानन उस जनता दल-सेक्युलर के नेतृत्व में सरकार बनाने की चाल चली जिसे उसने चुनाव प्रचार के दौरान खूब खरी-खोटी सुनाई थी। खुद राहुल गांधी ने जद-एस को भाजपा की बी टीम बताया था, लेकिन चुनाव बाद कांग्रेस ही उसकी बी टीम बन गई। क्या यह आदर्श लोकतांत्रिक तरीका है कि पहले नंबर वाले दल को सत्ता से दूर करने के लिए दूसरे नंबर वाला दल तीसरे नंबर वाले दल की अगुआई स्वीकार कर ले? क्या जनादेश का संदेश यही था? अगर कांग्रेस और जद-एस को यही करना था तो वे मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़े? क्या यह जनता के साथ छल नहीं कि एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े दल नतीजे आते ही एक हो जाएं? इन सवालों का कोई जवाब इसलिए नहीं, क्योंकि संविधान इस पर मौन है कि खंडित जनादेश की स्थिति में सरकार का गठन कैसे होना चाहिए? क्या राजनीतिक दलों का यह दायित्व नहीं कि वे तू तू-मैं मैं करने के बजाय खंडित जनादेश की हालत में सरकार गठन संबंधी नियम-कानूनों के अभाव को प्राथमिकता के आधार पर दूर करें?

यह न जाने कब से स्पष्ट है कि खंडित जनादेश में सरकार गठन की प्रक्रिया बिना नियमों वाले खेल में तब्दील हो जाती है और जोड़-तोड़, छल-छद्म के बिना सरकार नहीं बनती, लेकिन अपने स्वार्थों के चलते राजनीतिक दलों ने इसके लिए कभी कोई कोशिश ही नहीं की कि त्रिशंकु सदन में सरकार गठन के उचित तौर-तरीके तय हों। वे चुनाव पूर्व गठबंधन के मामले में भी इसीलिए उदासीन बने रहे ताकि उन्हें जनादेश की मनमानी व्याख्या करने का मौका मिल सके। इसमें दोराय नहीं कि कर्नाटक के राज्यपाल ने न केवल भाजपा के मन मुताबिक फैसला लिया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया कि येद्दयुरप्पा जल्द से जल्द मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लें, लेकिन उनके फैसले पर यह कहने का कोई मतलब नहीं कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी। आखिर वे लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं जो अपने समय राज्यपालों से मन मुताबिक फैसले कराते रहे और पसंदीदा दल की सरकारें बनवाते रहे? कर्नाटक के राज्यपाल ने तो ठीक वही किया जो कांग्रेस के जमाने के राज्यपाल किया करते थे। किसी दल और खासकर कांग्रेस को अपने विरोधी दल से यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वह उसकी तरह के काम न करे। भले ही सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस की यह शिकायत सुनने को तैयार हो कि सबसे बड़े दल को सरकार गठन के लिए क्यों बुलाया गया, लेकिन सभी को पता है कि गोवा और मणिपुर के चुनावों के बाद उसका सवाल यह था कि सबसे बड़े दल को सरकार गठन के लिए क्यों नहीं बुलाया गया? अच्छा हो कि कांग्रेस यह स्पष्ट करे कि वह तब सही सवाल पूछ रही थी या अब?

बेशर्मी से लीपापोती

वाराणसी के कैंट फ्लाईओवर हादसे की घटना जितनी दुखद है उससे भी अधिक अफसोसजनक है इस पर स्थानीय प्रशासन और सेतु निगम द्वारा की जा रही लीपापोती। फिलहाल, सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक राज मित्तल को हटा दिया है, लेकिन ऐसी ही कार्रवाई की आवश्यकता अभी कई अन्य लोगों पर भी है। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि हादसे में 15 की मौत हुई है जबकि राहत-बचाव में जुटे एनडीआरएफ ने दावा किया है कि 18 मौतें हुई हैं। आंकड़ों को लेकर विरोधाभासी तथ्यों से जिला प्रशासन सवालों के घेरे में है। हादसे की जांच आरंभ होते ही सेतु निगम की जो लापरवाही उजागर हो रही है, वह विस्मयकारी है।

> हादसे की जांच आरंभ होते ही सेतु निगम की जो लापरवाही उजागर हो रही है, वह आश्चर्यजनक है

हादसे के बाद जिस तेजी के साथ राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए, उतनी ही तेजी के साथ झूठ पर झूठ और सच पर पर्दा डालने के काम को भी अंजाम दिया जाने लगा। सेतु निगम के हटाए गए एमडी राजन मित्तल कहते रहे कि पुल पर बीम तैयार करने के बाद पुलिस को रूट डायवर्जन के लिए कहा गया था, लेकिन विभाग की ओर से जो पत्र जारी किए गए, उनमें डायवर्जन से संबंधित एक भी पत्र नहीं निकला। यदि पुल के नीचे आवागमन बंद होता तो लोगों की जान बच सकती थी। फ्लाईओवर के दो बीम गिरे कैसे, अब इसके विभिन्न पहलुओं को लेकर जांच आगे बढ़ रही है। प्रथम दृष्टया पिलर पर रखे बीम की बेयरिंग के फिसलने की बात सामने आ रही है। वास्तव में यदि सेतु निगम रूट डायवर्जन में रुचि लेता तो निसंदेह निरीह लोगों की जान और माल का नुकसान टाला जा सकता था, लेकिन अफसोस कि ऐसा नहीं किया गया।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पुलिसकर्मियों की आठ घंटे की ड्यूटी तय होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी?

आज का सवाल
क्या रमजान के दौरान जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान नहीं चलाने का निर्देश सही कदम है?

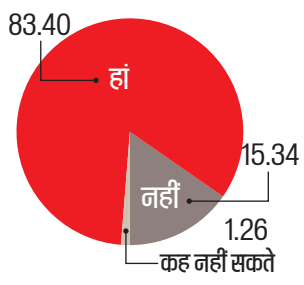

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y -हां, **N**-नहीं, **C**-कह नहीं सकते

परिणाम एसएमएस से प्राप्त नतीजों के साथ जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

नैतिकता के मनचाहे नियम

प्रदीप सिंह

जो कांग्रेस कल तक यह शिकायत कर रही थी कि गोवा, मणिपुर में सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहले मौका नहीं दिया गया वह अब ऐसे ही मौके को अनैतिक बता रही

कर्नाटक में सबसे बड़े विधायक दल के नेता बीएस येद्दयुरप्पा एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। विपक्ष और वाम बुद्धिजीवियों के एक वर्ग का आरोप है कि कर्नाटक में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आमजन यह जुमला सत्तर साल से सुन रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि कब लोकतंत्र की हत्या हो जाती है और कब लोकतंत्र बच जाता है? देश की सर्वोच्च अदालत आधी रात के बाद खुलती है और वहां गुहार लगाई जाती है कि लोकतंत्र की रक्षा कीजिए। सवाल है कि यह सिलसिला आखिर शुरू कब हुआ? कुछ लोगों को लगता है कि यह सब 2014 के बाद शुरू हुआ। अब ऐसे लोग और जो भी हों, लेकिन कमजोर याद्दाश्त वाले तो हैं ही। अगर गंगा की सफाई करनी है तो गोमुख/गंगोत्री से शुरू करना होगा गंगासागर से नहीं। लगभग उनसठ साल पहले, जी हां करीब छह दशक पहले की बात है। चार साल पहले की नहीं। साल 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर केरल राज्य बना। वहां 1957 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ। 127 सदस्यीय विधानसभा में ईएमएस नंबूदरीपाद के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी ने साठ सीटें जीतीं। पांच निर्दलियों के समर्थन से सरकार बनी। दुनिया में पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी लोकतांत्रिक चुनाव के जरिये सत्ता में आई। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहर लाल नेहरू, जिन्हें जनतंत्र का पुरोधा माना जाता था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद पर कोई और नहीं उनकी पुत्री इंदिरा गांधी विराजमान थीं। केरल सरकार भूमि सुधार और सामाजिक सुधार के दूसरे लोकप्रिय कदम उठाने लगी। पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस से विपक्षी दल की एक सरकार बर्दाश्त नहीं हुई। पहले कम्युनिस्ट पार्टी फिर निर्दलियों को तोड़ने की कोशिश हुई। इसके लिए कांग्रेस ने 'विमोचना समरम' यानी मुक्ति संघर्ष चलाया। इसके बाद भी जब एक भी विधायक नहीं टूटा तो 31 जुलाई 1959 को संविधान के अनुच्छेद 356 का पहली बार उपयोग/दुरुपयोग करके नंबूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। यह लोकतंत्र की स्थापना थी या हत्या? इसके बाद चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त करना कांग्रेस की सरकारों का राजनीतिक खेल हो गया।

सरकारिया आयोग की रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम तय किए उसके बाद इस पर थोड़ी लगाम लगी। जब तक कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा में बहुमत मिलता रहा, कोई समस्या नहीं थी। जैसे ही गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनने लगीं, समस्या शुरू हो गई। त्रिशंकु विधानसभा या लोकसभा में सरकार बनाने के लिए सबसे बड़े दल को बुलाया जाए या चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए साथ आए दलों को? कांग्रेस ने इसका बड़ा सीधा सा हल निकाला। उसके मुताबिक यह इस बात से तय होगा कि कांग्रेस को सत्ता में आने का मौका किस रास्ते से मिलता है? सबसे बड़ा दल कांग्रेस है तो नियम यह है कि राज्यपाल/राष्ट्रपति को सबसे बड़े दल को ही पहले सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेस चुनाव हार जाए और दूसरे दल के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा करे तो मौका उसे ही मिलना चाहिए। उसके हिसाब से ऐसा करना लोकतंत्र और संविधान की रक्षा है और इसके विपरीत आचरण लोकतंत्र और संविधान की हत्या है।

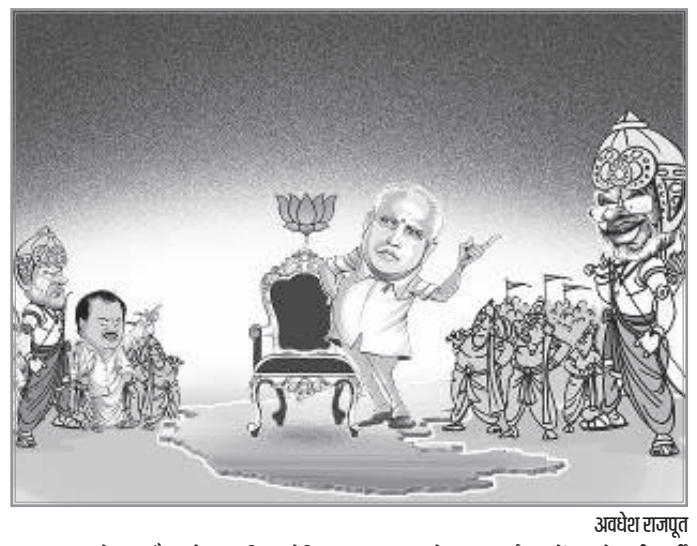

अवधेश राजपूत

अतीत से निकलकर अब निकट वर्तमान में आ जाते हैं। मान लेते हैं कि 2014 से पहले कांग्रेस ने जो भी किया वह सब संविधान सम्मत था। सारी गड़बड़ी पहले गोवा फिर मणिपुर और मेघालय में हुई। इन तीन राज्यों में कांग्रेस का तर्क था कि वह सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बावजूद उसे न बुलाकर राज्यपाल ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की। यह भी कि नरेंद्र मोदी तो आखिरकार लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए ही चुनकर आए हैं। इसलिए वह यह सब करवा रहे हैं। 2017 से कांग्रेस पूरे देश में घूम घूम कर कह रही थी कि संघी राज्यपालों ने सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का पहले मौका नहीं दिया। राज्यपाल ने अब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी को मौका दे दिया तो वही कांग्रेस आधी रात के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि राज्यपाल को रोकिए कि सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का मौका न दें, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी।

दूसरी ओर भाजपा के तर्क ठीक इसके विपरीत हैं। कल तक जो कांग्रेस कह रही थी, आज भाजपा कह रही है। अब बूझिए कि इनमें नैतिक कौन है? दिक्कत हो रही हो तो महाभारत का एक प्रसंग सुनिए: काफी मारकाट के बाद युद्ध लगभग आखिरी दौर में था। भीम और दुर्योधन का मल्ल युद्ध चल रहा था। गांधारी के आशीर्वाद से दुर्योधन की जंघा के अलावा पूरा शरीर वज्र का हो चुका था। भीम उसे हरा नहीं पा रहे थे। कृष्ण ने कहा, मझले भइया दुर्योधन की जंघा पर प्रहार कीजिए। दुर्योधन चिल्लाया, माधव यह युद्ध के नियम के विरुद्ध है और अनैतिक भी। कृष्ण का जवाब था जब बालक अभिमन्यु को आठ योद्धाओं ने घेर कर मारा। जब पांडवों के नवजात शिशुओं की धोखे से हत्या की गई तो युद्ध के नियम और नैतिकता याद नहीं आई। आज खुद पर संकट आया तो नियम और नैतिकता की याद आ रही है। कृष्ण ने भीम से फिर कहा, मझले भइया जंघा पर प्रहार करना धर्म विरुद्ध नहीं होगा। तो इस समय कांग्रेस की जंघा पर प्रहार हो रहा है।

अब जरा खरीद-फरोख्त की भी बात कर लें। जैसे ही कोई भी पार्टी यह आरोप लगाती है कि दूसरी पार्टी उसके विधायकों को खरीद रही है तो वह मान चुकी होती है कि उसके विधायक बिकने को तैयार हैं। तो जो बिकने को तैयार है वह खरीददार को नहीं देखता। उसकी नजर सिर्फ इस बात पर होती है कि कौन ज्यादा दाम दे रहा है। ऐसे में यह कैसे मान लिया जाए कि एक ही पक्ष दाम लगा रहा है। दूसरी बात यह कि फुटकर बिकने वालों पर नजर है, लेकिन थोक वाले का क्या? 222 विधायकों वाली वर्तमान विधानसभा में 38 विधायकों वाली पार्टी का नेता मुख्यमंत्री होगा। 78 विधायकों वाली पार्टी उसके पीछे खड़ी होगी और 104 विधायकों वाली पार्टी विपक्ष में बैठेगी। तो क्या यह मान लें कि सबसे कम विधायकों वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश किसी त्याग की भावना से हो रही है? क्या यह लोकतंत्र की जीत है। यदि इसका जवाब हां में है तो फिर लोकतंत्र की परिभाषा ही बदल जाएगी। त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति के लिए कोई तय नियम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसके हल की दिशा में कदम बढ़ाया था, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कम्पोजिट वोट का रास्ता सुझाया था। किसी को पहले या बाद में बुलाने की बजाय सदन अपना नेता चुने और उसकी सरकार बने। भविष्य के लिए यह एक रास्ता हो सकता है।

(लेखक राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

वुहान के बाद सोची की अहमियत

डॉ. स्वर्ण सिंह

भारत और रूस की विदेश नीतियों की दिशा में बढ़ते अंतर के बीच दोनों नेताओं की शिखर बैठक और अहम हो जाती है

सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ समुद्र तट पर स्थित खूबसूरत शहर सोची में अनौपचारिक शिखर वार्ता में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस शिखर वार्ता में दोनों नेता अंतरराष्ट्रीय मामलों पर अपने दूरगामी दृष्टिकोण को साझा करेंगे और अपनी विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी को सुदृढ़ कर प्रगति की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। इस शिखर वार्ता का फैसला अचानक नहीं हुआ। इसकी तैयारी काफी समय से चल रही थी। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर के मार्च में हुए रूस दौरे के बाद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के अलावा विदेश सचिव विजय गोखले के साथ ही भाजपा महासचिव राम माधव की रूस यात्राएं भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को सिरे चढ़ाने के सिलसिले में हुईं। 10 मई को मॉस्को में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पेट्रोशेव के साथ भारत के विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बातचीत में इस अनौपचारिक शिखर वार्ता की अंतिम रूपरेखा तैयार की गई। सवाल है कि यह शिखर वार्ता इस समय क्यों? इसका जवाब यही हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के चलते भारत को चीन और रूस से अपने संबंध सुधारने की जरूरत महसूस हो रही थी। इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ वुहान में हुई अनौपचारिक शिखर वार्ता के ठीक तीन सप्ताह बाद सोची वार्ता होने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति पुतिन से सितंबर, 2017 में श्यामन में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मिले थे और 2000 से चल रही सालाना औपचारिक शिखर वार्ता की शृंखला में जून, 2017 में सेंट पीटर्सबर्ग में मिले थे। उसके बाद दोनों नेताओं की कई बार फोन पर बातचीत हुई। आखिरी ऐसी बातचीत पुतिन के पुनर्निर्वाचन के बाद अप्रैल में हुई थी।

रासायनिक हथियारों के निषेध से संबंधित संगठन की सीरिया में बशर अल असद के रासायनिक हथियारों की जांच से जुड़ी बैठक में भारत शामिल तो रहा, लेकिन उसने प्रस्ताव के पक्ष-विपक्ष में कोई मतदान नहीं किया। तबसे भारत लगातार रूस से तालमेल बढ़ाने में सक्रिय रहा है। एक ऐसे समय जब भारतीय प्रधानमंत्री दो सप्ताह बाद सिंगापुर में हो रहे एशिया प्रशांत देशों के शांग्रीला डायलॉग में पहली बार शामिल होंगे तब रूसी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात काफी उत्सुकता जगाने वाली है। यह भी ध्यान रहे कि दोनों नेता अगले माह चीन के शहर छिंगताओ में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में, जुलाई में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में और फिर नवंबर में अर्जेंटीना में

हो रहे जी-20 शिखर सम्मेलन में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति पुतिन वर्ष 2000 से चल रहे भारत-रूस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने अक्टूबर में भारत आएंगे।

इन सभी पूर्व नियोजित मुलाकातों के बावजूद सोची शिखर सम्मेलन के पीछे भारत की क्या जरूरत हो सकती है? पहली बात तो यह है कि भारत और रूस की विदेश नीतियों की दिशा में बढ़ता अंतर चिंता का कारण बना हुआ है। रूस का चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ता हालिया रुझान भारत को दक्षिण एशिया में भी हाशिये की ओर धकेल रहा है। रूस हमेशा से भारत के लिए रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता रहा है, परंतु अब वह चीन और पाकिस्तान को हथियार मुहैया करा रहा है। एक बेहद जटिल तकनीक वाली लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल, एस400ट्रायंफ पाकिस्तान को मिलने की संभावना भारत के लिए सामरिक अस्थिरता बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। भारत भी इस मिसाइल को लेने की कोशिश में है, लेकिन अगस्त 2017 में बनाए गए अमेरिकी कानून 'काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शंस एक्ट' के चलते यह सौदा अधर में लटक गया है। इस कानून का असर दो अरब डॉलर वाले अकूला-क्लास पनडुब्बी सौदे के साथ-साथ रूसी फ्रिगेट, हेलीकॉप्टरों और हाल में शुरू किए गए संयुक्त उपक्रमों पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा रूसी रक्षा उपकरणों के 48 कलपुर्जों को भारत में बनाने की योजना भी खटाई में पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का रूस से रक्षा उपकरणों का आयात पिछले पांच वर्षों में 79 प्रतिशत से घटकर 62 प्रतिशत रह गया है। पश्चिमी देशों से किए गए कई रक्षा सौदों के चलते रूस से रक्षा सामग्री का आयात और कम हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में रूस से रक्षा उपकरण आयात की कोई भी बड़ी योजना क्रियान्वित नहीं हो पाई है। अमेरिका के उक्त कानून का असर रूस की हथियार निर्माता कंपनियों पर भी पड़ेगा। जाहिर है कि इस अनौपचारिक सम्मेलन में अंतरराष्ट्रीय मामलों के साथ-साथ भारत और रूस की सदाबहार दोस्ती में पुरानी गर्मजोशी लाना ही सबसे ऊपर होगा। इसके लिए रक्षा सहयोग में नई जान फूंकना जरूरी हो जाएगा। इसके अलावा दोनों नेताओं की निजी नजदीकी और आपसी तालमेल पर भी जोर रहेगा। दुनिया की बड़ी शक्तियों के दमदार नेता अब अनौपचारिक वार्ता के जरिये ही मामलों को सुलझाने को वरीयता देने लगे हैं।

प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में इसकी शुरुआत उनके शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही हो गई थी जिसमें दक्षिण एशिया के सभी नेताओं को निमंत्रित किया गया था। इस साल गणतंत्र दिवस समारोह पर भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दस नेताओं को एक साथ आमंत्रित किया गया। 2015 में साल की शुरुआत राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ 'चाय पर चर्चा' से हुई तो साल के अंत में क्रिसमस पर प्रधानमंत्री काबुल से लौटते वक्त अचानक लाहौर में रुक गए। वहां नवाज शरीफ की नाती की शादी में शामिल होना उनकी व्यक्तिगत कूटनीति वाली शैली का ही उदाहरण था। सोची में भी उनका यही अंदाज देखने को मिलेगा। इसमें भले ही सभी मामले न सुलझें, लेकिन व्यक्तिगत गर्मजोशी और तालमेल का प्रदर्शन जरूर देखने को मिलेगा। दोनों देशों के बदलते रुख के कुछ परिणाम तो पहले ही देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से शिथिलता के शिकार हुए भारत-रूस द्विपक्षीय व्यापार व्यापार में बीते वर्ष 21 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई और इसका भारत के यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन से रिश्तों पर अच्छा असर पड़ रहा है। हाल में राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा एकाएक ईरान परमाणु समझौते को खारिज कर देने और इजरायल में अपना दूतावास यरूशलम स्थानांतरित कर देने से पश्चिम एशिया में रूस की अहमियत अचानक और बढ़ गई है। साफ है कि इन बदलते हुए भू-राजनीतिक समीकरणों में भारत सामरिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर चलते हुए रूस के साथ रिश्तों को नए सिरे से साधने की कोशिश करेगा।

(लेखक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कूटनीति के प्रोफेसर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

अच्छे की चाह

कुछ अच्छा करने की चाह जिंदगी को सफल और सार्थक बनाती है। हर महीने एक पौधा लगाना या हर रोज किसी अजनबी को मुस्कराहट देना संभवतया आपके जीवन में भारी बदलाव न ला सके, लेकिन वे आपकी उस जिंदगी को बरकरार रख पाने में सफल होते हैं, जिसकी चाह लगभग हर व्यक्ति के भीतर विद्यमान होती है। हम ऐसा करने के लिए संकल्पित भी होते हैं, क्योंकि इससे जिंदगी को बदलने और उसे बेहतर बनाने की आधारभूमि तैयार होती है। एक सच यह है कि हम वैसे ही बन जाते हैं, जैसाकि हम सोचते रहते हैं। जैनधर्म में प्रतिक्रमण का प्रावधान है। उसमें हम अच्छे संकल्पों को बार-बार दोहराते हैं और वे हमारे अवचेतन मस्तिष्क में व्यवस्थित हो जाते हैं। आदमी का अच्छा या बुरा होना भाग्य, परिस्थिति या कोई दूसरे व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। यह सब कुछ घटित होता है शुभ-अशुभ भावों से। हम, आप, सभी जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मैं क्या होना चाहता हूं, इसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूं। आज हर आदमी सुख की खोज में खड़ा है। और उस थके-हारे इंसान को प्रतिबोध देते हुए खलील जिब्रान को पढ़ना अच्छा लगता है, जो लिखते हैं-मैं भी कहता हूं कि जीवन सचमुच अंधकारमय है, यदि आकांक्षा न हो। सारी आकांक्षाएं अंधी हैं यदि ज्ञान न हो। सारा ज्ञान व्यर्थ है यदि कर्म का ज्ञान न हो। जब तुम प्रेम से प्रेरित होकर कर्म करते हो तब तुम स्वयं से बंधते हो, एक-दूसरे से बंधते हो, भगवान से बंधते हो।

ऐसा नहीं है कि आज का आदमी समय के साथ चलना न चाहे, बुरे आचरण छोड़कर अच्छी जिंदगी का सपना न देखे, खराबी को खराबी समझने कि लिए तैयार न हो। सोचना यह है कि हम गहरे में जमे संस्कारों को कैसे सुधारें? जड़ तक कैसे पहुंचे? बिना जड़ के सिर्फ फूल पत्तों का क्या मूल्य? पतझड़ में फूल पत्ते सभी झड़ जाते हैं मगर वृक्ष कभी इस वियोग पर शोक नहीं करता। उसके पास जड़ की सत्ता सुरक्षित है जिससे वसंत आने पर पुनः वृक्ष फूल पत्तों से लहलहा उठता है। आज हमें भी संकल्पों को मुकाम तक पहुंचाने के लिए मूल्यों को स्वयं में सहेजना होगा, बाहरी अवधारणाओं को बदलना होगा, जीने की दिशा को मोड़ देना होगा। तभी बंधन ढीले पड़ेंगे और निर्माण का रास्ता साफ-सुथरा बन सकेगा।

ललित गर्ग

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

सच्चाई के करीब

डॉ. देवेंद्र कुमार का लेख आंबेडकर के विचारों के विपरीत राजनीति उन लोगों की आंखें खोलने वाला है जो बाबा साहब का नाम लेते हुए दलित-मुस्लिम गठजोड़ का नारा लगाते हैं। बाबा साहब ने लिखा है कि इस्लाम में न तो सभी के लिए समानता है, न भाईचारा। सार्वजनिक भातृत्व भाव अपनाने वाले बौद्धमत को उसने सब जगह नष्ट किया। बाबासाहब ने अपने अनुयायियों को सदा सावधान किया कि हिंदुओं के प्रति रुष्ट रहने के कारण मुस्लिम राजनीति का मोहरा न बन जाएं। बंगाल में उनकी पार्टी के एक बड़े नेता जोगेंद्र नाथ मंडल ने उनकी सलाह को ठुकरा कर मुस्लिम लीग का दामन थाम लिया। मंडल को जिन्ना ने अक्टूबर 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल में लीग की ओर से शामिल किया। पाकिस्तान बनने के तत्काल पूर्व सिलहट जिले में हुए जनमत संग्रह में जोगेंद्रनाथ ने दलितों में पाकिस्तान के पक्ष में वोट देने के लिए प्रचार किया। कुछ दलित मतदाता प्रभावित भी हुए। सिलहट पाकिस्तान को मिल गया। मंडल पाकिस्तान के प्रथम कानून तथा श्रम मंत्री बनाए गए, किंतु जल्द ही उन्हें बाबा साहब की अपील की सत्यता समझ आ गई। आंबेडकर ने कहा था कि जिन्ना अपने हित में दलितों का इस्तेमाल कर लेंगे और बदले में कुछ नहीं देंगे, बल्कि इस्लामी उत्पीड़न का शिकार भी बनाएंगे। ऐसा ही हुआ। आखिरकार तीन साल बाद अपनी इज्जत, संपत्ति, धर्म और लाखों दलितों के प्राण लुटाने के बाद जोगेंद्रनाथ पाकिस्तान सरकार से त्यागपत्र देकर मुंह छुपाते हुए भारत लौटे। दलित-मुस्लिम गठजोड़ का उनका स्वप्न छिन्न-भिन्न हो चुका था। मायावती, जिग्नेश मेवाणी वगैरह कुछ सीख सकें तो सीख लें। पाकिस्तान के बाद कश्मीर का उदाहरण भी सामने है। 1956 में वहां सफाई हेतु बुलवाए गए दलितों की दो पीढ़ियां वहां गुजर गईं, लेकिन उन्हें आज तक कुछ बुनियादी अधिकार नहीं मिले हैं।

अजय मित्तल, मेरठ

ऐसे थे आंबेडकर

डा. देवेंद्र कुमार का लेख, आंबेडकर के विचारों के विपरीत राजनीति, पढ़ा। इन्होंने बाबा साहब के विचारों के उलट दलित- मुस्लिम गठजोड़ बनाने का प्रयास कर रहे लोगों पर तथ्यों के साथ सवाल खड़ा किया है। बाबा साहब ने अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में कभी भी दलितों और मुस्लिमों के एकता की बात नहीं की। यदि आंबेडकर इस्लाम से इतने ही प्रभावित होते तो उन्होंने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया होता। बौद्ध धर्म का हमेशा से हिंदुत्व से जुड़ाव रहा है और इसी क्रम में गौतम बुद्ध को हिन्दू धर्म में ईश्वर का अवतार माना गया है। बाबा साहब ने हमेशा राष्ट्र की एकता व अखंडता कायम रखने की बात कही और यहां तक कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान किए जाने का कड़ा विरोध किया था। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बाबा साहब की राय नहीं मानी।

स्नेह प्रभा झा, नोएडा

अस्पतालों में सुविधाएं

सरकारी अस्पतालों में स्थिति बदतर है। वहां शुल्क भले ही कम है, किंतु अच्छी और संतोषजनक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। प्राइवेट अस्पतालों में शुल्क बेहद ज्यादा है, मगर वे बेहतरीन सुविधाओं से लैस हैं तथा इलाज भी जल्दी हो जाता है। गरीब व्यक्ति महंगे निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करवा सकता, इसलिए वह सरकारी अस्पतालों से अच्छे इलाज की उम्मीद रखता है। केंद्र व राज्य सरकारों को सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास करना चाहिए, ताकि समाज के हर तबके के लोग अच्छा इलाज करवा सकें।

सौरभ पाठक, ग्रेटर नोएडा

न बढ़ाएं बच्चों का तनाव

परीक्षा परिणाम को लेकर केवल बच्चे ही नहीं, उनके अभिभावक भी चिंतित रहते हैं। परिणाम को लेकर बच्चों के चेहरे मुरझाए से लगते हैं। हम क्यों यह नहीं समझते कि शिक्षा का क्षेत्र कोरा व्यापार बनकर रह गया है। बच्चों को रेस का घोड़ा बना लिया गया है और उन्हें चाबुक मार कर भगाया जाता है। बच्चे पढ़ाई के बोझ तले दबे नजर आते हैं। उनका बचपन छिन गया है। उन पर दुनिया भर की आकांक्षाओं का बोझ मां- बाप ही डाल देंगे तो वो मासूम जाएंगे कहां? अक्सर कुछ अभिभावक आपसी बातचीत में अपने बच्चों के नंबर का बखान करते रहते हैं। मगर उन अभिभावकों का क्या जिनके बच्चे सामान्य होते हैं। उनके लिए आज के समय में जीना दूभर हो जाता है। सबके ताने सुनने पड़ते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि हर बच्चा अव्वल नहीं आ सकता। क्या किसी के कहने पर गुलाब का फूल गेंदे का फूल बन जाएगा, नहीं ना...। फिर क्यों बच्चों को वह बनाने की कोशिश की जाती है, जो वह नही होते। जिन अभिभावकों के बच्चे पढ़ाई में सामान्य होते हैं उन्हें उनके भविष्य की बड़ी चिंता होती है, मगर वो करेंगे क्या? सच तो यह है कि जिसमें प्रतिभा है वह खुद अपनी राह खोज लेगा। परिणाम के समय बच्चे खुद बहुत तनाव में रहते हैं। उनका तनाव बढ़ाने के बजाए उनके साथ मजबूत ढाल बन कर खड़ा होना चाहिए। परिणाम जो भी हो हमें यह देखना चाहिए कि बच्चे ने मेहनत कैसी की है। अगर मेहनत ठीक रही है तो परिणाम थोड़ा -बहुत इधर-उधर हो सकता है। इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अधिक नंबर से ही व्यक्ति सफल नहीं होता है, व्यक्ति की सफलता उसकी योग्यता पर निर्भर करती है। यानी उसकी जानकारी कैसी है। अपने बच्चे पर अपनी उम्मीदों का बोझ न थोपें, कम नंबर लाए तो भी उन्हें गले लगाएं। अगर बच्चा पढ़ाई में सामान्य है तो क्या हुआ, हर बच्चे में कुछ न कुछ खास होता है।

shilpasurana48@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

रमजान संघर्षविराम के पहले दिन ही लश्कर के संदिग्ध आतंकियों ने हाजिन में एक कश्मीरी युवा की हत्या कर दी। पीड़ित परिवार के लिए रमजान में कोई राहत नहीं।

गौरव सी सावंत@gauravcsawant

बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात बेहद रोमांचक